अपनाएं भारत मुक्ति का महामार्ग

उत्तराखंड में अगर सेना नहीं होती तो क्या हुआ होता ? यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा. इस प्रश्न का ऐसा अर्थ निकलता है कि राज्य और केंद्र सरकार लोगों की सुरक्षा करन में असमर्थ हैं. यह बार-बार सिद्ध भी हो चुका है. चाहे वह आतंकी हमला हो या बम विस्फोट, सेना के बिना सरकार के अपंग होने की बात स्पष्ट हुई है. जैसा कि २६ नवंबर २००८ के मुंबई हमले में १० आतंकवादियों ने महाराष्ट्र व केंद्र सरकार को लगभग बंधक ही बना डाला था. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और तत्कालीन और वर्तमान गृहमंत्री आर.आर. पाटिल ने त्यागपत्र देने का नाटक किया. जनाक्रोश को काबू में करने के लिए कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आम जनता की आंखों में धूल झोंकी. लोगों ने भी स्वयं को धोखा देते हुए २००८ के आतंकी हमले में दिखाई गई पलायनवादी वृत्ति का एक तरह से समर्थन कर उन्हें ही चुना. पुनः विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री और आर. आर. पाटिल गृहमंत्री बने. सरकार देवभूमि म बाढ़ आने से जैसे सुन्न ही हो गई. यदि सेना न होती तो लाखों लोगों की मौत होती. इसका अर्थ यह कि केंद्र व राज्य सरकार का जनता की सुरक्षा करने में कोई योगदान नहीं रहा. अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हर कदम पर जनता को लूटन में लगा हुआ दिखाई दे रहा है. वे तनख्वाह भी जनता की ही खाते हैं. सभी क्षेत्रों में आज के राजनीतिक नेता और प्रशासकीय अधिकारी अकर्मण्य, संवेदनहीनता से भरे और स्वार्थ के वशीभूत दिखाई देते हैं.

वास्तविक रूप से देखा जाए तो बाढ़ जैसी आपदा में जनता की मदद करना सेना का काम नहीं है. यह राज्य सरकार तथा केंद्रीय गृहविभाग का काम है, किंतु राज्य व केंद्र सरकार की प्रशासनिक मशीनरी ऐसे समय में हमेशा ही फेल हो जाया करती है, तो फिर ऐसी मशीनरी का उपयोग हो क्या है ? उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए.

सन १९९१ में मैं सांसद बना. तब से आज तक मैं सरकार तथा जनता को भारत पर आने वाले संकटों के संबंध में सतत आगाह या सचेत करता रहा हूं. बाबरी मस्जिद गिराने का अमेरिकी षड़यंत्र और उससे हिंदू-मुस्लिम गृहयुद्ध भड़काने की करतत के बारे में २८ अक्टूबर १९९२ को ही प्रधानमंत्री को लिखित रूप से जानकारी दी थी. उसके द्वारा मुंबई के माफिया तत्वों को बचाने के लिए सुधाकर राव नाईक को मुख्यमंत्री पद से निकालने के षड़यंत्र के का परदाफाश भी मैंने पहले ही किया था., शरद पवार कांग्रेस को तोड़ेंगे, क्यों कि भाजपा को सत्ता में लाने का यह अमेरिकन षड़यंत्र है, यह बात सोनिया गांधी का सचिव रहने के दौरान ही मैंने एक वर्ष पूर्व ही लिखित रूप से सूचित कर दी थी. सन ९८ में वाजपेयी और नवाज शरीफ गलबहिया डाल रहे थे, तब ९८ के दिसंबर माह में सेना के हाथ न बांधने की तथा पाकिस्तानी आतंकवादी टोलियों के भारत में आक्रमकरूप से घुसने की जानकारी भी लिखित रूप से उन्हें दी, किंतु इस ओर से लापरवाही बरती गई. इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी घुसपैठियों ने आधे कारगिल पर कब्जा कर लिया. भविष्य में होने वाली वारदातों के बारे में मैं यदि पहले से बता रहा था तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं था. यह तो मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुमान लगाने में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए मैंने गुप्तचर विभाग में एक उत्तम इंटेलिजंस ऑफीसर के रूप में नाम कमाया. आज के नादान राज्यकर्ताओं में दूरदृष्टि, ज्ञान का अभाव है. वे देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का

आकलन नहीं कर पाते. देश के शत्रु कौन और मित्र कौन हैं, यह उन्हें मालूम नहीं है. सभी बड़े बापों की औलादें राजनेता बनी घूमती हैं. उनका मिट्टी, रक्त और फौलाद से कभी संबंध नहीं आया. ऐसे लोगों को सर पर उठाए जनता नाच रही है.

मैंने लोकसभा के अपने पहले भाषण में ही मांग की थी कि, सरकारी सेवा में चुने गए लोगों के लिए दो वर्ष सेना में सेवाएं देना अनिवार्य करना चाहिए. दूसरी ओर ७ वर्षों तक सेना में काम करने के बाद ही केंद्र व राज्य पुलिस दल में भर्ती करनी चाहिए. सीधी भती न हो. इससे पूलिस दल का प्रशिक्षण और भर्ती पर होने वाला खर्च बचेगा. साथ ही सेना दल का पेंशन पर होने वाला खर्च भी बचेगा. उसी तरह से अपने सैनिकों के संबंध में उत्पन्न संकट भी हल होगा. हमारे सैनिक उम्र के ३२ से ३८ वर्ष की उम्र में सेवामुक्त होते हैं और दर-दर नौकरी ढूंढते भटकते हैं. मेरा आग्रह है कि सेना में काम कर चुके सैनिकों को सीधे राज्य और केंद्र की सरकारी नौकरियों में लिया जाए. सेना इस बात के लिए तैयार है किंतु राज्यकर्ता और नौकरशाही इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रही है. २६ नवंबर २००८ के आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र पुलिसने फोर्स वन गठित किया. मैंने उस समय विनती की कि, सेना के जवानों को प्रतिनियुक्ति या स्थायी रूप से फोर्स वन में समाविष्ट किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस मांग को ठुकरा दिया, क्यों कि पुलिस भर्ती में पैसे खाने को कैसे मिलेंगे ? केंद्र सरकार ने भी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आवश्यकता न होने पर भी नई गुप्तचर संसथा नेशनल इंटेलिजंस एजेंसी का निर्माण किया. उस समय भो मैंने सेना के जवानों को इसमें शामिल करने की मांग की थी. उसे भी ठुकरा दिया गया. अंततोगत्वा आतंकवाद के खिलाफ लड़नेका अनुभव तो सेना के ही पास है न! इसका ही परिणाम है कि देश में करोड़ों रु. खर्च करने के बावजूद आतंकवाद या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई सक्षम मशीनरी नहीं है. जो राज्यकर्ता अनेकों बार विविशि हो कर लाखों लोगों के मरने के बाद भी, आने वाली प्रलय में शिकार होने वालों के प्राण नहीं बचा सकते, वे इस देश की रक्षा कैसे करेंगे ? इसलिए आज हम नई इस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हैं. महंगाई, वैश्वीकरणके कारण बढ़ती ही जा रही है, किंतु जनता उससे अनभिज्ञ है. आज के राजनैतिक दल तो चोर हैं ही, साथ में देश की पूरी अर्थव्यवस्था को विश्व बैंक और विदेशी पूंजीवादी ताकतों के हाथों में सौंप कर इस देश को गुलाम बना डाला है. पूंजीवादी ताकतों के सबसे बड़े एजेंट नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जा कर क्या नाटक किया, यह सभी ने देखा है. अब जो हजारों करोड रुपए चार ट्रकों में भरे हुए मुंबई में पकड़े गए, वे गुजरात जा रहे थे. किसके लिए ? इस पर अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है. पर यही काला पैसा और काला धंधा देश को लगा हुआ कैंसर है और गरीबों का शोषणकर्ता भी है. क्यों कि काला धन अमीर चोरों के पास ही रहता है. राज्यकर्ता गोरे पूंजीवादियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. मनमोहन सिंह ने 51 प्रतिशत एफडीआई लाकर भारत की सभी बड़ी कंपनियों और बैंकों को नई इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. इसे देशद्रोही कृत्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ? इस पूरी व्यवस्था का कोई नया विकल्प खड़ा न हो इस दृष्टि से तीसरे मोर्चे का नाटक खड़ा किया जा रहा है. ऐन वक्त पर कांग्रेस फ्रंट और शिवसेना की यति के साथ मैच फिक्सिंग कर छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर को बेचने वाली मंडली पूंजीवादियों के छिपे एजेंट ही हैं.

सभी क्षेत्रों में, सभी प्रमुख दलों की सरकारों की असफलता जनता पर जाहिर हो रही है. क्यों कि

इस देश में सरकार नहीं वरन् दलाल ही सक्रिय हैं. जिस लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षा राज्यकर्ताओं द्वारा पूरी नहीं होती, वह देश गुलामों का देश होता है. उसके कारण इस ग़लामी से देश को मुक्त करने के लिए वैकल्पिक फ्रंट या मोदी जैसे घोषणा बहादुर पैदा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मूलभूत विचार, कार्यक्रम, और संगठन द्वारा ही हो सकेगा. 'इसलिए ही मेरे द्वारा पहले कहेनुसार आज के प्रमुख राजनीतिक दलों को त्याग कर नवोदित राजनीतिक दलों को खड़ा करना चाहिए. यही भारतमुक्ति का महामार्ग है.'

लेखकः ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईटःwww.sudhirsawant.com
मोबा . नंः ९९८७७१४९२९